ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of the Press briefing **Held at 1615 Hours 04.08.2014**

Shri Randeep Surjewala addressed the media today.

श्री रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम हाल ही में सम्पन्न हुए कामनवेल्थ गेम्स में पदक पाने वाले व भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम हार्दिक मुबारकबाद और शुभकामनाएं देते हैं। देश के सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की और बेहतर प्रदर्शन की एशियाड खेलों व ओलंपिक खेलों में जो आगे आने वाले समय में आएंगे उनमें उनके उज्जवल भविष्य और बेहतर प्रदर्शन की कामना भी करते हैं।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि आज मैं आपका ध्यान गुजरात प्रदेश से आए एक सनसनीखेज समाचार और घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ। सोलह गांव के नौवीं और दसवीं के छात्र एवं छात्राएं–लड़के और लड़कियां– गुजरात में स्कूल जाने के लिए पुल के अभाव में तैर कर नदी पार करके स्कूल जाने को अभिशप्त हैं। पिछले सात सालों से नर्मदा जिले और छोटा नागपुर जिले के बीच हिरण नदी पर यह सब अबोध बच्चे और इनके अभिभावक एक पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। पर चौतरफा विकास में व्यस्त गुजरात की सरकार का ध्यान इन अबोध लड़कों और लड़कियों के अमानवीय हालात पर आज तक नहीं जा पाया है। खास तौर से इन बच्चों में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हैं जो प्लास्टिक के लिफाफों में किताबें और नदी के तट पर दोबारा से कपड़े बदलने के लिए मजबूर हैं। यह सब छात्राएं अपनी मांगे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती आनन्दी बेन पटेल जी के समक्ष रख चुके हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को ना उनकी सुरक्षा की चिन्ता है और ना ही उनके भविष्य की और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से एक बार फिर हम गुजरात की पहली मुख्यमंत्री का ध्यान हम अबोध बालकों का इस अमानवीय कहानी की ओर आकर्षित करना चाहते हैं ताकि इसका व्यापक हल गुजरात की सरकार निकाल सके।

और इससे भी आगे और इसी तरह का एक और खुलासा गुजरात में शिक्षित महिलाओं की दयनीय स्थिती को लेकर है। एक ओर गुजरात की सरकार महिला सशक्तीकरण पखवाड़ा मना रही है तो दूसरी ओर 2011 की जनगणना के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि

15 वर्ष से 34 वर्ष की आयु के बीच गुजरात की महिलाओं का 70.34 प्रतिशत ऐसा है जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है।

इनके साथ–साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार का ध्यान प्रशासनिक सेवा में प्रणाली, पद्धति एवं प्रारूप को लेकर और भाषाई भेदभाव को लेकर शहरी और ग्रामीण आंचल के विद्यार्थियों में व्यापक असमानता को लेकर जो हजारों–लाखों विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। उसी परिपेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ जो घोषणा आज सरकार के द्वारा सदन के पटल पर की गई है। उन सब लाखों विद्यार्थियों की जिनमें से ज्यादातर उस प्रान्त से आते हैं जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद चुनकर आए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा इत्यादि। पहली उनकी मांग थी कि सी–सैट की परीक्षा जो है उसको खारिज किया जाए और दूसरी उनकी मुख्य मांग थी कि सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के द्वारा किया जाने वाला हिन्दी अनुवाद गूगल के माध्यम से इस प्रकार की भाषा में किया जा रहा है कि अर्थ का अनर्थ उन सवालों के जवाबों को देते हुए बच्चों के सामने आ रहा है।

आज जो घोषणा प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में राज्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर की है, मैंने भिन्न–भिन्न छात्र संगठनों के मित्रों से हमने बात की है। उन सबका यह कहना है कि यह घोषणाएं, एक अंग्रेजी का दो पंक्तियों की कहावत है Too little – too late.

चार या पांच महत्वपूर्ण विषय इन घोषणाओं के उपरान्त भी छात्रों के सामने आज भी खड़े हैं।

1. क्या सरकार छात्रों की सी–सेट परीक्षा को खारिज करने की मांग को नकार चुकी है?
2. क्या मात्र एक वर्ष अतिरिक्त 2011 के छात्रों को देने से जिनको दो वर्ष पहले भी कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद यूपीए सरकार ने दिए थे, उससे दूरगामी तौर से इस समस्या का हल निकल पाएगा?
3. अगर अंग्रेजी Comprehension के विषय के अंकों को फाइनल ग्रेडेशन में जोड़ना नहीं है तो उस विषय के पेपर लेने का क्या औचित्य रह जाता है? क्योंकि यह Qualifying परीक्षा तो है नहीं Mains की तरह।
4. एक सरकारी दमन चक्र के, लाठियों और अश्रु गैस के गोलों के शिकार छात्र लगभग 30–40 दिन से इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक आंदोलनरत हैं। सरकार पहले सोती रही और प्राथमिक परीक्षा से मात्र 20 दिन पहले लिया गया यह निर्णय क्या ग्रामीण आंचल के उन सभी छात्रों को संपूर्ण तैयारी करने का एक व्यापक मौका दे पाएगा या फिर सरकार को छात्राओं

और छात्रों की वास्तुस्थिती को देखकर परीक्षा की तारीखों में उन्हें और मौका देने के लिए फेरबदल करने की आवश्यकता थी।

5. और पॉचवा सबसे महत्वपूर्ण भाषाई भेदभाव का, अंग्रेजी के मुकाबले में जो छात्रों के मन की एक भावना थी उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और उस बारे में यूपीएससी को किस प्रकार के निर्देश एवं हिदायतें दी गई हैं?

सरकार को अपना निर्णय और स्पष्ट करने की आवश्यकता है और इन पांचों बिन्दुओं पर छात्रों, शिक्षकों और दूसरे सब संबंधित पक्षों से वार्ता कर सर्व–सम्मत हल निकालने की आवश्यकता है जिसमें माननीय जितेंद्र सिंह जी और मोदी सरकार विफल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सरकार से विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि वो इन पांचों बातों का संज्ञान ले, छात्राओं और छात्रों से दोबारा मंत्रणा करें, सभी पक्षों से मंत्रणा करें, संसद को विश्वास में लें और फिर एक दुरगामी सर्व–सम्मत निर्णय निकाल कर देश की जनता के समक्ष रखें।

On the question of the reaction of the Congress party that it was only two months ago that the changes were made in the UPSC, now why the Congress party was behind it, now the Congress party is in opposition and is opposing it for the sake of opposing it? Shri Randeep Surjewala said qua the pattern of examinations and the objections that were received from various student organizations, it is the Indian National Congress and its UPA government which was then in power which proceeded to grant, as I have already pointed out, on the intervention of the Congress Vice President Shri Rahul Gandhi Ji two chances up to the year 2014 to all the students. It is on the demand of the students that the then Prime Minister former Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji proceeded to constitute a Committee to have a comprehensive look at the entire pattern of examination. We have heard this criticism in hindsight many times or you did that - that is why we are doing so. I thought NDA came to power because they felt that the policies of UPA's alliance were not 100% accurate. It is only when the problem was noticed that UPA proceeded to grant two years' chance which was not enough and that is why UPA ordered a comprehensive review of the entire C-SAT examination. Today the problem is -

(1) Students are demanding scrapping of C-SAT that is one issue – students are also stating that the entire translation that is being done through Google by UPSC and the government is lopsided and at time nonsensical putting the students belonging to Hindi and regional language at a severe disadvantage by the announcement made today by the Hon'ble Minister in PMO office. He has only extended chance by a year. He has only said that they will be English comprehension marks will not be counted for purposes of gradation

and that is why we have placed five important questions raised by various student unions including BJP own student union for consideration of the government as to if the marks are not going to be included for gradation, why have the examination.

(2) Whether the government is proceeding to reject the demand of the students for scrapping C-SAT. What would happen to meaningful sensible translations of even non-English questions that various students have been demanding which is currently being done in literal nonsensical fashion through Google and not through translators?

(3) What would happen to the larger scheme that the students have been demanding qua discrimination with Hindi and other regional languages as also the so-called urban rural divide and how does the government propose to solve it. There are all questions that government must answer.

On a question as to why the Congress party is playing flip-flop and turning its back on the issue of Insurance Bill in view of the fact even the NCP pointed out that it was originally in 2008 the UPA had planned this Bill, Shri Surjewala said I would respectfully say it is not correct. All that Indian National Congress wants is that all stakeholders must be appropriately consulted and taken on board. Indian National Congress has always been pro-investment but it has always spoken about inclusive growth with investment and if the interests of lakhs of people involved in the Insurance sector is going to be jeopardized then necessary balancing has to be done and there is no final Yes or No. Consultations are still on. We do stand committed to provide constructive support in national interest on all issues to the BJP government. However, we shall continue to articulate the voice of the poor as also the voice of those workers and people involved in the Insurance Sector also.

On the question of reaction of the Congress party on the statement of Shri Janardan Dwivedi on the comments of Jagmit Singh Brar, Shri Surjewala said I have not heard Shri Janardan Dwivedi Ji's statement in the context of which he has said so. I would refer back to him and revert back to you.

On a question as to why the Congress party is opposing Insurance Bill since the crux is to up the FDI from 26% to 49%, Shri Surjewala said it is a misnomer with due regard to say that Indian National Congress is opposing the Bill. We only want a balanced consideration of all issues including involvement of all stakeholders prior to taking a considered rational reasonable decision.

On the question of the reaction of the Congress party that a lady Additional Judge in Gwalior had to resign, Shri Surjewala said the incident is unfortunate. The President of All India Mahila Congress has already made a detailed statement on the issue today. It is the onerous responsibility of the Chief Justice of India and his brother Judges in the Supreme Court to give adequate protection to the lady Judge, seize the entire record, conduct a short time bound investigation, hear both the parties as per already defined procedure and punish the guilty person.

On another question as to whether the Congress party will oppose the Insurance Bill in its present form, Shri Surjewala said as already explained, matter is under deliberations within the party. We have had a look at the Bill as is being proposed by the government and we shall take an appropriate call by considering various contours of the matter.

एक अन्य प्रश्न पर कि मौजूदा स्थिती में कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं तो क्या ऐसी स्थिती में श्रीमती प्रियंका गांधी जी को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, श्री सुरजेवाला ने कहा कि जहां तक श्रीमती प्रियंका गांधी जी का प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब अनेकों बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से भिन्न–भिन्न प्रवक्ता दे चुके हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अपनी भूमिका राजनीति में स्वयं निर्धारित कर रखी हैं जो दो संसदीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली तक सीमित है। इसके अलावा बाकी सब काल्पनिक है और हम नकारते हैं।

In the related question to the above and in context of the Congress party sitting in the opposition, Shri Surjewala said this is not the first time that the Indian National Congress has sat in opposition nor is it the last attack on the Indian National Congress and its ideology. We are determined and capable of defending all attacks and will continue to work to win the hearts of people of India with stronger vigour with even more dedication and in a more humble manner.

Sd/-
(Tom Vadakkan)
Secretary
Communication Deptt.